एक बहुपक्षीय विकल्प, एशिया के माध्यम से

लेखक-मुकुल सनवाल (संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

09 जनवरी, 2020

"नई व्यवस्था की रूप-रेखा, जहाँ मुख्य खिलाड़ी के रूप में भारत और चीन स्थित हैं, को पश्चिमी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।"

200 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में फिर से बड़ी हो गई हैं। जहाँ एक तरफ भारत और चीन अपने सीमा विवाद को हल करने में लगे हुए हैं, वही दूसरी तरफ एशिया मूल्यों से विभाजित दुनिया को बहुपक्षीय विकल्प प्रदान करने में लगा हुआ है।

कहा जाता है कि 'एशियन सेंचुरी' शब्द 1988 में चीनी नेता देंग शियाओपिंग और पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच 1962 में हुई भारत-चीन सीमा संघर्ष के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए उत्पन्न हुआ था। यह दोनों देशों के फिर से उभरने, एक नई व्यवस्था को आकार देने के लिए तकनीकी क्षमता को अपनाने के प्रयास को दर्शाता है, साथ ही यह इनके सभ्यतागत मूल्यों को दर्शाता है जो पश्चिम के लोगों से अलग हैं। उदाहरण के लिए, मध्य वर्ग की आय में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ पश्चिम की त्रासदी इस बात की पुष्टि करती है कि वैश्विक विभाजन अब मूल्यों पर आधारित है।

वन बेल्ट, वन रोड

परिचय

- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को वर्ष 2013 में शुरू किया था। इसका मकसद राजमार्गों, रेलवे लाइनों, बंदरगाहों और समुद्री रास्तों के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना है।
- इस परियोजना ना के लिए चीन ने अरबों डॉलर अपने 60 साझीदार देशों पर खर्च किए हैं। श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान जैसे उसके साझीदार देश उसकी इस परियोजना के तहत् उसके कर्ज में डूब चुके हैं।

चीन ने 2013 में, 15% वैश्विक धन प्राप्त करने के बाद, बहुपक्षीय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की घोषणा की और 2014 में, वैश्विक शासन प्रतिमान को चुनौती देते हुए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की शुरुआत की। 2015 में, उभरते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की, एक अलग वैश्विक सतत् विकास ढाँचा तैयार किया और अपना वर्चस्व स्थापित किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुपक्षवाद को दरकिनार करते हुए 'एशियाई शताब्दी' को मान्यता दी है और चीन, भारत तथा इंडो-पैसिफिक निर्माण के साथ इसका प्रत्यक्ष लेन-देन इसी को तथ्य को सत्यापित करता है। अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों को केवल राजनीतिक और प्रक्रियात्मक दृष्टि से परिभाषित करना, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से खुद को अलग रख विकासशील देशों पर बोझ को बढ़ाना और व्यापार शासन में बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल करने के लिए अन्य देशों को मजबूर करना वर्तमान बहुपक्षवाद के औपनिवेशिक मूल को दर्शाता है, जिसके कारण अब इसे न सिर्फ एशिया के बल्कि अपने समर्थकों के भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

नई रूपरेखा

निर्णायक बदलाव एशियाई विकास इंजन और एशियाई प्रौद्योगिकी दोनों का जवाब देता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा देश-विशिष्ट कार्यों से हटकर विखंडित प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रही है। वैश्विक व्यापार नियमों में कंपनी-विशिष्ट चिंताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जहाँ देशों के बजाय वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था धन और शक्ति के निर्धारक हैं।

दुनिया पर यू.एस.-निर्धारित राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के लागू होने के कारण केवल कुछ मुट्ठी भर देशों ने ही Huawei

5G तकनीक पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की, रूस से गैस पाइपलाइन बनाने वाली कंपनियों पर प्रतिबंधों को लेकर यूरोप में नाराजगी को बढ़ावा दिया, ईरान पर प्रतिबंधों ने भारत के हितों को प्रभावित किया है, दीर्घकालिक संबंधों को प्रभावित किया है और दोनों प्रणालियों के बीच एक अन्तर्हित चयन का निर्माण किया है।

चीन, जो कभी पूरी तरह से उपनिवेशित नहीं हुआ था और जल्दी अमीर होने का इच्छुक था, ने एक समझौता संधि के सहमत लक्ष्यों से अलग 'सामान्य हितों' के आधार पर एक नए बहुपक्षवाद को प्रमुखता से शुरुआत की है। देश युरेशियन बाजारों में कनेक्टिविटी और एकीकरण के लाभों के कारण बाजार आधारित ब्याज दरों के साथ भी नेटवर्क आधारित विकास प्रक्रिया के रूप में बीआरआई (यह 72 देशों और दुनिया की 70% आबादी को शामिल करता है) का समर्थन करते हैं। भविष्य में बीआरआई फंडिंग का आधा हिस्सा बहुराष्ट्रीय निगमों और बहुपक्षीय बैंकों से आएगा, जो कठिनाइयों को हल करने में उनकी मदद करेगा।

बीआरआई की क्षमता

बीआरआई नई वैश्विक संस्था के निर्माण के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करता है क्योंकि इसका दायरा बहुपक्षीय संधियों जितना विस्तृत है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय बैंकों से समर्थन के साथ बीआरआई में बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, वैश्विक आर्थिक प्रशासन में चीन की भूमिका को बढ़ाते हुए, Renminbi के अंतर्राष्ट्रीयकरण में योगदान दे रहे हैं।

डिजिटल लेनदेन में दुनिया के लीडर के रूप में चीन बीआरआई देशों में ब्लॉक चेन-आधारित वित्तीय अवसंरचना विकसित कर रहा है और डॉलर पर भरोसा किए बिना डिजिटल लेन-देन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक-चेन मुद्रा की खोज कर रहा है और इस प्रकार यह यू.एस. की प्रमुखता को कम कर रहा है।

इस तरह के बदलाव की गति और पैमाने के साथ, बढ़ते एशिया चीन से सावधान रहता है और चाहता है कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल हो, जो कि एक विशाल बाजार होने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनने की ओर अग्रसर है। अमेरिकी सेना की 'एशिया में धुरी' (Pivot to Asia) के साथ, चीन समस्याओं से बचने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए इच्छुक है।

सीमा मुद्दों पर हालिया भारत-चीन शिखर सम्मेलन में 'सीमा मुद्दों पर अंतिम समाधान के लिए एक रोडमैप' तैयार करने का संकल्प लिया गया, साथ ही भारत ने अमेरिकी विरोध के बावजूद 5 जी ट्रायल के लिए हुआवेई (Huawei) के विकल्प का चयन किया है। भारत सरकार ने हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड सहित सभी आवेदकों को भाग लेने की अनुमति दी है।

नए मूल्य

नई व्यवस्था की रूप-रेखा, जहाँ मुख्य खिलाड़ी के रूप में भारत और चीन स्थित हैं, को पश्चिमी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। 2018 में, चीन अमेरिका में वस्तुओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, साथ ही यह भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार भी रहा है। सभी बड़े देशों का इन तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं और वे क्षेत्रीय आधार पर सीमित क्षेत्रीय सहयोग में भाग लेते रहते हैं। यहाँ तक कि नाटो ने भी हाल ही में चीन के उदय के निहितार्थ पर चर्चा की है, भारत की

मुख्य बिंदु

- रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिए सितंबर, 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्तावित 'वन बेल्ट, वन रोड' 1400 अरब डॉलर की परियोजना है। ओबीओआर को 35 वर्ष में पूरा किए जाने का लक्ष्य है, जब 2049 में चीनी गणराज्य की 100वीं वर्षगाँठ मनाई जाएगी।
- विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिए है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।
- यहाँ 'बेल्ट' से तात्पर्य सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट से है, जो तीन स्थल मार्गों से मिलकर बनी है- (i) चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग। (ii) चीन को मध्य व पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूमध्यसागर से जोड़ने वाला मार्ग। (iii) चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर से जोड़ने वाला मार्ग।
- 'रोड' से तात्पर्य 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड से है, जिसका निर्माण दक्षिण चीन सागर व हिंद महासागर के माध्यम से चीन के तट से यूरोप में व्यापार करने तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन के तट से दक्षिण प्रशांत तक व्यापार करने के लिए किया गया है।

तरह चीन भी किसी सामूहिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अमेरिका और चीन दोनों ने भारत के साथ रणनीतिक मुद्दों पर नियमित रूप से उच्च स्तरीय चर्चा की है, ताकि इसकी जनसांख्यिकीय, तकनीकी और संसाधन क्षमता को भविष्य के वैश्विक शक्ति का हिस्सा माना जा सके।

अब सवाल उठता है कि इस बदलाव के निहितार्थ क्या हैं? एशिया ने दो-तिहाई वैश्विक जीडीपी का गठन किया है और उपनिवेशवाद एशियाई दिग्गजों की गिरावट का कारण बना। इनका फिर से उदय 'पश्चिमीकरण' के वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा नहीं है। सीमा समस्या भी उपनिवेशवाद का अवशेष है न कि आक्रामकता का परिणाम।

जाहिर है अमेरिका, चीन और भारत भविष्य में अपने सभ्यता के मॉडल को बनाए रखेंगे। एशिया में मतभेद अतिव्यापी प्राथमिकताओं पर केंद्रित होंगे, जैसे सुरक्षा (आधिपत्य बनाए रखने के लिए अमेरिका का प्रयास), आर्थिक (कनेक्टिविटी, बाजार और विकास पर चीन का जोर) और समान टिकाऊ विकास (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भारतीय नेतृत्व वाला ढाँचा, जिसे नागरिकों की भलाई के लिए बनाया गया है)।

इन गलियारों से जाल बिछाएगा चीन

1. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
2. न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज
3. चीन-मध्य एशिया-पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा
4. चीन-मंगोलिया-रूस आर्थिक गलियारा
5. बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा
6. इंडोचाइना-प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा

चीन के लिए महत्त्वपूर्ण क्यों?

- विशेषज्ञों का मानना है कि 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल चीन की आर्थिक कूटनीति का खाका है।
- विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चीन स्वयं को अकेला महसूस करता है क्योंकि वह जी-7 में शामिल नहीं है और केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित है।
- उनका मानना है कि अपने आर्थिक विस्तार को जारी रखने के लिये चीन को एक नीति की आवश्यकता थी और 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल ने उसकी इस मंशा को बखूबी पूरा किया है।

भारत के लिए लाभ

- प्रतिस्पर्धी नेटवर्क स्थापित करने के लिये आज भारत में संसाधनों की कमी है। इसलिए वह OBOR के उन घटकों में भाग लेने के लिए उपयुक्त हो सकता है, जो प्रमुख बाजारों और संसाधनों की आपूर्ति के लिए भारतीय कनेक्टिविटी में सुधार ला सकते हैं।
- इसमें 60 देशों के साथ-साथ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी), ब्रिक्स के नव विकास बैंक, सिल्क रोड फंड, सीआईसी के समर्थन वाले कोष और संभवत: एससीओ विकास बैंक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जुड़ रहे हैं और साथ ही इसे ऑस्ट्रेलिया का भी समर्थन हासिल है।
- यदि भारत को 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना है, तो एशियन मार्केट को बिना एकीकृत किए यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इस परियोजना में शामिल होकर भारत को एशियाई बाजारों के एकीकरण में हिस्सेदार बनना चाहिए और उसका लाभ भी उठाना चाहिए।

भारत पर प्रभाव

- भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि चीन का वन बेल्ट, वन रोड का सपना साकार हो गया, तो चीन निर्विवाद रूप से एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा, जिससे भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को धक्का लग सकता है।
- पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) भी ओबीओआर का ही हिस्सा है।
- भारत, चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। भारत की नजर में यह कॉरिडोर उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाला है।
- ओबीओआर के माध्यम से चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को नई दिशा देना चाहता है जो इसने दक्षिण एशिया में काम करना भी शुरू कर दिया है,

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. चीन की "वन बेल्ट, वन रोड" योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2013 में प्रस्तावित की गई इस परियोजना को 2050 में चीनी गणराज्य की 100वीं वर्षगांठ पर पूरा करना है।
2. यह चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग है।
3. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला चीन, पाकिस्तान कॉरिडोर इस योजना का ही हिस्सा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements in the context of China's One Belt, One Road Scheme.

1. The project proposed in the year 2013 is to be completed in 2050 on the 100th anniversary of the Republic of China
2. It is a route connecting China, Central Asia and Europe.
3. China-Pakistan Corridor passing through Pakistan Occupied Kashmir is part of this Scheme.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

नोट : 8 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: "वर्तमान वैश्विक चुनौतियों में भारत-चीन-रूस त्रिकोण की भूमिका इनके गौरवशाली इतिहास की भांति महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।" इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

The role of the Indo-China-Russia triangle in current global challenges can prove to be as important as their glorious history. To what extent you agree with this statement? Analyze.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।